at the Udyogamandal Unit are being explored. One of the alternatives under scrutiny is a proposal to set up a caprolactam project.

उन गैर-सरकारी कोयला खान कम्पनियों की बकाया राशियों की अदायगी जिनकी सम्पत्ति राष्ट्रीयकरण के समय अर्जित की गयी थी

5794. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी कोयला खान कम्पनियों के 1974 में अर्जन के समय हजारों कोयला सप्लायरों की सम्पत्ति और एजेंसियां भी अधिग्रहीत की गई थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन लोगों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिनकी हानि हुई थी भुगतान आयोग भी नियुक्त किया गया तथा जांच करने के बाद कोयला सप्लायरों को प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे ; और

(ग) यदि उपरोक्त भागों के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो कितने लघु कोयला सप्लायरों को मुआवजे के लिए प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे तथा बंगाल कोल कम्पनी और अन्य कम्पनियों के कितने कोयला सप्लायरों को मुआवजा अदा किया गया और कितनों को अभी अदा किया जाना है तथा शेष सप्लायरों को भुगतान कब तक करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में दी गई खान की परिभाषा के अनुसार किया गया था। खान मालिकों को देय राशि इन अधिनियमों की अनुसूची में दिखाई गई है ।

(ख) धनबाद और कलकत्ता में भुगतान आयुक्त नियुक्त किये गये हैं जिनका काम इन दोनों अधिनियमों में दी गयी अपेक्षा के अनुसार दावेदारों और मालिकों को भुगतान करना है ।

(ग) भुगतान आयुक्तों की नियुक्ति कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अधीन की गई है और उनके सामने एक लाख से अधिक दावे दायर किये गए हैं । मांगी गई सूचना को एकत्र करने में अत्यधिक काम करना पड़ेगा और इस प्रकार एकत्र आंकड़े आदि अभीष्ट परिणामों की तुलना में लाभदायक नहीं होंगे। फिर भी, प्राप्त सूचना के अनुसार, 34 कोकिंग कोयला खान मलिकों और 40 अकोकिंग कोयला खान मलिकों के मामले में सप्लायरों के स्वीकृत दावों का अधिनियमों की व्यवस्थाओं के अनुसार भुगतान कर दिया गया है । बंगाल कोयला कम्पनी के मामले में सप्लायरों के किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया है । चालू अनुमानों के अनुसार कोकिंग कोयला खानों के मंजूर दावों का भुगतान तीन वर्षों के अन्दर और अकोकिंग कोयला खानों से संबंधित दावों का एक वर्ष के अन्दर भुगतान हो जाने की संभावना है ।

Commissioning of Projects at HAL, Pimpri, Maharashtra

5795. SHRI R. K. MHALGI : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) what were the proposed dates of commissioning of the following projects HAL, Pimpri, Maharashtra;